Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC)

भारतीय अर्थव्यवस्था

(उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ सहित)

भाग-2

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

Code: UPPM15

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC)

भारतीय अर्थव्यवस्था

(उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ सहित)

भाग–2

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501
टोल फ्री : 1800-121-6260
Web : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिये निम्नलिखित पेज को "like" करें
www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
www.twitter.com/drishtiias

UPPCS DLP विषय सूची (Contents)

9.	**कृषि**	**5-53**
9.1	आर्थिक विकास में कृषि का योगदान	5
9.2	हरित क्रांति : विशेषताएँ, प्रभाव तथा द्वितीय हरित क्रांति	7
9.3	कृषि विपणन, भंडारण और ढुलाई	10
9.4	न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़े मुद्दे	17
9.5	खाद्य सुरक्षा एवं बफर स्टॉक	21
9.6	सार्वजनिक वितरण प्रणाली : उद्देश्य एवं सीमाएँ	26
9.7	प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायिकी	29
9.8	कृषि से संबंधित अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रक	30
9.9	कृषि साख	34
9.10	कृषि से संबंधित तकनीकी मिशन एवं योजनाएँ	36
9.11	उत्तर प्रदेश में कृषि, बागवानी और पशुपालन	44
10.	**भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग**	**54-75**
10.1	खाद्य प्रसंस्करण : अर्थ, कार्यक्षेत्र एवं महत्त्व	54
10.2	खाद्य प्रसंस्करण : स्थान निर्धारण	57
10.3	आपूर्ति शृंखला : ऊर्ध्व एवं अधोप्रवाह आवश्यकताएँ	58
10.4	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की चुनौतियों एवं सुधार के लिये कदम	61
10.5	खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से संबंधित योजनाएँ एवं संस्थान	63
10.6	उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	71
11.	**आर्थिक एवं सामाजिक विकास**	**76-103**
11.1	आर्थिक एवं सामाजिक विकास की अवधारणा	76
11.2	आर्थिक विकास के मापक	78
11.3	सामाजिक-आर्थिक विकास के मापक	82
11.4	आर्थिक विकास की रणनीति	91
11.5	आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक	93
11.6	आर्थिक संवृद्धि तथा मानव विकास	99
12.	**समावेशी संवृद्धि तथा सामाजिक न्याय**	**104-134**
12.1	समावेशी संवृद्धि : आशय एवं अवधारणा	104
12.2	सामाजिक न्याय एवं सामाजिक समावेशन	105

12.3 वित्तीय समावेशन 107
12.4 जनसंख्या संबंधी मुद्दे एवं संबद्ध समस्याएँ 111
12.5 गरीबी और विकासात्मक विषय 114
12.6 बेरोज़गारी 122
12.7 क्षेत्रीय असंतुलन : कारण एवं समाधान 127
12.8 प्रव्रजन : कारण एवं समाधान 128

13. सतत् विकास **135-147**
13.1 सतत् विकास : अर्थ एवं अवधारणा 135
13.2 सतत् विकास से संबंधित कारक 136
13.3 सतत् विकास हेतु भारत के प्रयास 141
13.4 सतत् विकास लक्ष्य और भारत 142

14. नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के मुद्दे **148-183**
14.1 नगरीय क्षेत्र के मुद्दे : शहरीकरण से उपजी समस्याएँ 148
14.2 शहरी अवसंरचना : आवास, स्वच्छता और अवसंरचना विकास योजनाएँ 152
14.3 ग्रामीण अवसंरचना : आवास, स्वच्छता और अवसंरचना विकास योजनाएँ 162
14.4 उत्तर प्रदेश में नगरीकरण 178

15. योजनाएँ एवं विविध **184-225**
15.1 केंद्र सरकार की योजनाएँ 184
15.2 उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएँ 196
15.3 उत्तर प्रदेश में मानव संसाधन एवं कौशल विकास 207
15.4 विविध 213

16. आर्थिक अवधारणाएँ तथा शब्दावलियाँ **226-231**

अध्याय
9

कृषि
(Agriculture)

भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि लगभग 50% आबादी कृषि एवं उससे संबंधित कार्यों में लगी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आजीविका का एक महत्त्वपूर्ण साधन है। आर्थिक सर्वेक्षण, 2017–18 की रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में इसका योगदान लगभग 16% है, जबकि वर्ष 1950–51 में यह हिस्सा लगभग 51% था। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से देखें तो कृषि की भागीदारी उद्योग तथा सेवा क्षेत्र की तुलना में कम है। खाद्यान्न उत्पादन जहाँ 1951–52 में मात्र 52 मिलियन टन था, वहीं 2016–17 में यह बढ़कर 275.7 मिलियन टन हो गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जहाँ कृषि क्षेत्र में विकास दर 4.72% थी, वहीं नौवीं, दसवीं एवं ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास दर क्रमशः 2.44%, 2.30%, 3.3% रही। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर का लक्ष्य 4% रखा गया।

9.1 आर्थिक विकास में कृषि का योगदान
(Contribution of Agriculture in Economic Development)

कृषि क्षेत्र का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में महत्त्वपूर्ण योगदान है। वित्तीय वर्ष 1950–51 में यह लगभग 51% था तथा वित्तीय वर्ष 2011–12 में यह लगभग 14.2% रह गया। राष्ट्रीय आय के आकलन की नई शृंखला (आधार वर्ष 2011–12) के आधार पर 2016–17 में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का सकल मूल्य संवर्द्धन (GVA) में योगदान 17.4% था, जबकि वर्ष 2017–18 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का हिस्सा कुल जीवीए (वर्तमान कीमतों पर) में 16.4 होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। सकल मूल्य संवर्द्धन में कृषि के प्रतिशत योगदान में कमी अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्त्व में गिरावट को नहीं दर्शाती है, अपितु यह केवल अर्थव्यवस्था के द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों की सापेक्षिक तीव्र वृद्धि को दर्शाती है।

आर्थिक विकास में कृषि का योगदान निम्नलिखित है-

- **रोज़गार:** भारत में कृषि रोज़गार का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। भारत में आज भी लगभग 50% कार्यशील जनसंख्या कृषि क्षेत्र में कार्यरत है।
- **बढ़ती हुई जनसंख्या के लिये खाद्यान्नों की आपूर्ति:** भारत में कृषि क्षेत्र के उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल खाद्यान्नों का उत्पादन लगभग 251.57 मिलियन टन रहा, जो कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में बढ़कर 275.7 मिलियन टन (चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार) हो गया है। अतः वर्तमान में भारत को अपनी विशाल जनसंख्या की खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आयात पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है।
- **औद्योगिक विकास के लिये कृषि क्षेत्र का महत्त्व:** कच्चे माल के आपूर्तिकर्त्ता के रूप में कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र की संवृद्धि के लिये मुख्य रूप से महत्त्वपूर्ण है। कृषि क्षेत्र के द्वारा औद्योगिक कच्चे मालों, जैसे- कपड़ा उद्योग को कपास, तेल उद्योग को तेल बीजों, चीनी उद्योग को गन्ने की आपूर्ति की जाती है। यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को कृषि उत्पादों के रूप में कच्चा माल उपलब्ध कराता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्त्वपूर्ण योगदान:** कृषि भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी महत्त्वपूर्ण योगदान देती है। भारत चाय, जूट, काजू, तंबाकू, कॉफी और मसाले आदि का निर्यात करता है। ये सभी कृषि वस्तुएँ भारत के कुल निर्यात का एक बड़ा प्रतिशत साझा करती हैं।
- **गरीबी उन्मूलन में महत्त्वपूर्ण भूमिका:** भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में आधी से अधिक श्रम शक्ति कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। कृषि आज भी निम्न आय वर्ग एवं निर्धन व्यक्तियों का जीवन आधार है। कृषि क्षेत्र खाद्य सुरक्षा का मुख्य अस्त्र है।

समाहित हैं। बागवानी फसलों का कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पादन योगदान में महत्त्वपूर्ण योगदान है। बागवानी उत्पादों की बढ़ती हुई मांग तथा कृषि में महत्त्वपूर्ण योगदान के कारण ही बागवानी फसलें प्राथमिकता का क्षेत्र बन रहा है। बागवानी फसलों के व्यवसायीकरण एवं कृषि के विविधीकरण से प्रदेश की महत्त्वपूर्ण बागवानी फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल में विस्तार, पुराने आम, अमरूद एवं आँवला के अनुत्पादक बागों के जीर्णोद्धार, गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री का उत्पादन, फसल तुड़ाई उपरांत प्रबंधन एवं अन्य कार्यक्रमों को कार्यान्वित कराकर प्रदेश में बागवानी के विकास के लिये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिकता दी जा रही है।

उत्तर प्रदेश के उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा फल, शाकभाजी, आलू, पुष्प, मसाले, औषधि एवं सगंध पौधों, पान विकास के साथ-साथ सहायक उद्यम के रूप में मौन पालन, मशरूम उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण, पान की खेती के लिये विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित कर सतत् विकास हेतु प्रयास किये जा रहे है। उत्तर प्रदेश में एकीकृत बागवानी विकास मिशन, ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई की स्थापना, औषधीय पौध मिशन, अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में बागवानी विकास, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास हेतु कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के सुनियोजित विकास को प्रोत्साहित करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2017 प्रख्यापित की गई है, जिसके द्वारा पूंजीगत अनुदान, ब्याज रियायतें, गुणवत्ता एवं प्रमाणीकरण, बाज़ार विकास, अनुसंधान एवं विकास तथा निर्यात प्रोत्साहन के साथ-साथ प्रदेश में उद्योगों की स्थापना हेतु अनेक रियायतें एवं छूट प्रदान की गई है।

परीक्षोपयोगी महत्त्वपूर्ण तथ्य

- जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक (59.3%) जनसंख्या नियोजित है। राज्य के कुल कर्मचारियों में किसान 29.0% एवं कृषि श्रमिक 30. 3% है।
- भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिये ग्रामीण निर्धनता प्रभावी कारण है क्योंकि गरीबी किसानों को कृषि में तकनीक के प्रयोग एवं निवेश को हतोत्साहित करती है।
- NSSO के वर्ष 2014 के अनुमानों के अनुसार जुलाई 2012-जून 2013 (कृषि वर्ष) के दौरान कृषि में विनियोजित ग्रामीण परिवारों का हिस्सा 57.8% था।
- वर्ष 2009–10 के आँकड़ों के अनुसार सोयाबीन कृषि का सर्वाधिक क्षेत्र मध्य प्रदेश में था। वर्ष 2013-14 के आँकड़ों के अनुसार भी मध्य प्रदेश (6.30 मिलियन हेक्टेयर) शीर्ष सोयाबीन कृषि क्षेत्र वाला राज्य था। एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक एट ए ग्लैंस, 2016 के आँकड़ों के अनुसार भी निम्न स्थिति रही-

सोयाबीन की फसल	राज्य		
3 शीर्ष उत्पादक राज्य	1. मध्य प्रदेश (4.91 मिलियन टन)	2. महाराष्ट्र (2.10 मिलियन टन)	3. राजस्थान (1 मिलियन टन)
क्षेत्राकुमार तीन शीर्ष राज्य	1. मध्य प्रदेश (59.06 लाख है)	2. महाराष्ट्र (37.74 मिलियन टन)	3. राजस्थान (12.05 मिलियन टन)
उत्पादकता के आधार पर	1. तेलंगाना (1037 किग्रा./हे.)	2. मध्य प्रदेश (831 किग्रा./हे.)	3. महाराष्ट्र (829 किग्रा./हे.)

- विश्व में कपास के प्रति उत्पादन में प्रथम, ऑस्ट्रेलिया (2.038 किग्रा./हे.), द्वितीय तुर्की (1620 किग्रा./हे.) एवं तृतीय ब्राज़ील (1524 किग्रा./हे.) का स्थान है।
- वर्ष 2011–12 में राज्यों में गेहूँ उत्पादन में शीर्ष राज्य क्रमशः हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार थे, जबकि वर्ष 2016–17 के चतुर्थ अग्रिम अनुमानों के आँकड़ों के अनुसार गेहूँ के तीन शीर्ष उत्पादक राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश (30.1 मिलियन टन), मध्य प्रदेश (17.9 मिलियन टन), पंजाब (16.4 मिलियन टन) है।

- कृषि सांख्यिकी, 2015 के अनुसार 2012-13 (अनंतिम) में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल लगभग 13.99 करोड़ हेक्टेयर था। जबकि कृषि मंत्रालय की वर्ष 2017–18 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल शुद्ध बोया क्षेत्र 140.1 मिलियन हेक्टेयर, कुल फसल क्षेत्र 198.4 मिलियन हेक्टेयर, फसल सघनता 142%, शुद्ध बोया गया क्षेत्र कुल फसली क्षेत्र का 42% तथा शुद्ध सिंचित क्षेत्र 68.4 मिलियन हेक्टेयर है।
- भारत में औसत फसल गहना वर्ष 2009–10 में 135.79% वर्ष 2012–13 में 139% तथा वर्ष 2017–18 में 142% (कृषि मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार) है।
- भारत में फसल बीमा के लिये पहला प्रयास व्यापक फसल बीमा योजना (CCIS) 1 अप्रैल, 1985 में किया गया।
- वर्ष 2005–06 में 5 मई, 2005 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM) प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में बागवानी क्षेत्र का विकास एवं उत्पादन में बढ़ोतरी करना है। यह योजना दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की गई थी।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में (11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक) गेहूँ, चावल और दलहन का अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। वर्तमान में चावल, गेहूँ, दलहन, मोटे अनाज व वाणिज्यिक फसलें इसके अंतर्गत आच्छादित है, परंतु इसमें तिलहन को सम्मिलित नहीं किया गया है।
- बारहवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का लक्ष्य 4% रखा गया था।
- बजट 2018-19 में भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। वर्ष 2018-19 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को कुल ₹ 58,080 करोड़ आवंटित किये गए हैं।
- भारत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रारंभ **13 जनवरी, 2016** को खरीफ फसल से हुआ।
- 'हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर' भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा प्रकाशित की जाती है।
- राष्ट्रीय हॉर्टीकल्चर मिशन को दसवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था।
- राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य बागवानी क्षेत्र में ऊँची संवृद्धि प्राप्त करना, शस्योत्तर व्यवस्था करना तथा मानव संसाधन विकास सुनिश्चित करना है।
- फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं कीमत आयोग द्वारा किया जाता है।
- भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन वर्ष 2007–08 में रबी फसल से प्रभावी हुआ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत गेहूँ, चावल एवं दालों को शामिल किया गया था।
- 'ऑपरेशन फ्लड' का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। भारत में वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में दुग्ध व्यवसाय के विकास के लिये वर्ष 1970 में 'ऑपरेशन फ्लड' अभियान चलाया गया था।
- ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती एक ऐसी उत्पादन प्रणाली है, जो मानव स्वास्थ्य, मृदा एवं पर्यावरण के अनुकूल है।
- नेफेड (NAFED) का संबंध कृषि विपणन से है।
- भूमि विकास बैंक के अंतर्गत दीर्घकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
- भारत में एगमार्क एक्ट वर्ष 1937 में लागू किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का आरंभ वर्ष 1998–99 में किया गया था।
- नेशनल एकेडेमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट हैदराबाद में स्थित है। भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झाँसी में स्थित है।
- 'अमृत क्रांति' का संबंध 'नदी जोड़ो परियोजना' से है। 'बादामी क्रांति' का संबंध मसाला उत्पादन से है।
- 'भारत में हरित क्रांति', 1966 के जनक एमएस स्वामीनाथन थे तथा तत्कालीन कृषि मंत्री सी. सुब्रमण्यम एवं तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की इसमें विशेष भूमिका थी। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली पंतनगर को माना जाता है।
- भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिये भूमि संसाधन विभाग 21 अगस्त, 2008 से राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है।
- सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये एमएस स्वामीनाधन द्वारा प्रयोग में लाई गई थी।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. 4 जुलाई, 2018 से धान का प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थित मूल्य (एमएसपी) 2018-19 के दौरान है? **UPPCS (Pre) 2018**

(a) ₹ 1,5 50 (b) ₹ 1,650
(c) ₹ 1,750 (d) ₹ 1,450

2. निम्नलिखित कॉफी उत्पादक देशों को उनके कॉफी उत्पादन (2016) (मात्रा) को अवरोही क्रम मे व्यवस्थित करें और नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर का चयन करें- **UPPCS (Pre) 2018**

1. कोलंबिया 2. वियतनाम
3. ब्राजील 4. इंडोनेशिया

कूट:

(a) 4, 3, 2, 1 (b) 3, 2, 1, 4
(c) 2, 4, 3, 1 (d) 3, 1, 2, 4

3. भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिये निम्नलिखित में से कौन प्रभावी कारण है? **UPPCS (Mains) 2016**

(a) ग्रामीण निर्धनता
(b) शहरी निर्धनता
(c) कुशल श्रमिक
(d) शहर से गांवों की ओर पलायन

4. राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण कार्यालय के 2014 अनुमानानुसार, ग्रामीण परिवारों में कृषि में विनियोजित ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत है- **UPPCS (Mains) 2016**

(a) 52.5% (b) 55.6%
(c) 57.8% (d) 59.2%

5. राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ किया गया? **UPPCS (Mains) 2016**

(a) मई 2004 में
(b) मई 2006 में
(c) मई 2007 में
(d) मई 2005 में

6. निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन-सी एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सम्मिलित नहीं थी? **UPPCS (Mains) 2016**

(a) तिलहन (b) चावल
(c) गेहूँ (d) दालें

7. हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है- **UPPCS (Mains) 2016**

(a) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से
(b) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से
(c) उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद् से
(d) भारतीय विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् से

8. न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये- **UPPCS (Mains) 2016**

1. यदि बाज़ार मूल्य ज़्यादा है तो किसान सरकार को बेचेंगे।
2. यह किसानों की पैदावार के लिये न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करती है।
3. यह खाद्य सुरक्षा मिशन में सहायता प्रदान करती है।
4. यह किसानों के लिये अत्यंत लाभदायक है, क्योंकि वे अपनी पैदावार पर ज़्यादा बड़ा लाभ कमाते हैं।

इनमें से-

(a) 1, 2 एवं 4 सही हैं।
(b) 2, 3 और 4 सही हैं।
(c) 2 और 4 सही हैं।
(d) 2 और 3 सही हैं।

9. निम्नलिखित में से किस वर्ष में 'राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम' प्रारंभ किया गया था? **UPPCS (Pre) 2016**

(a) 2008 ई. (b) 2009 ई.
(c) 2010 ई. (d) 2011 ई.

10. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? **UPPCS (Pre) 2016**

(a) उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण।
(b) सुधारीकृत उत्पादन तकनीक का निदर्शन।
(c) साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना।
(d) फसलों की नई विकसित किस्मों का प्रचार-प्रसार करना।

11. सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित करें तथा सूचियों के नीचे दिये कूट से सही उत्तर चुनिये: **UPPCS Pre 2016**

सूची-I	सूची-II
A. विटिकल्चर	1. सब्ज़ी-खेती
B. वेजीकल्चर	2. मछली पालन
C. पिसीकल्चर	3. वृक्षों की कृषि
D. ओलेरीकल्चर	4. अंगूर की खेती

कूट:

	A	B	C	D
(a)	1	2	3	4
(b)	4	3	2	1
(c)	3	2	1	4
(d)	4	1	2	3

12. भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है लगभग- **UP (RO/ARO) Pre 2016**
(a) 12 करोड़ हे. (b) 16 करोड़ हे.
(c) 14 करोड़ हे. (d) 17 करोड़ हे.

13. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: **UP (RO/ARO) Pre 2016**
1. किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 2001 में शुरू की गई थी।
2. यह योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त और समयानुकूल साख समर्थन प्रदान करती है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

14. 'सदाबहार क्रांति' भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रयोग में लाई गई- **UPPCS (Mains) 2015**
(a) नॉर्मन बोरलॉग द्वारा
(b) एमएम स्वामीनाथन द्वारा
(c) राज कृष्णा द्वारा
(d) आरकेवी राव द्वारा

15. हरित क्रांति संबंधित है- **UPPCS (Pre) 2015**
(a) मोटे अनाज के उत्पादन से
(b) दलहन उत्पादन से
(c) गेहूँ उत्पादन से
(d) तिलहन उत्पादन से

16. निम्न में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है? **UPPCS (Pre) 2015**
(a) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्
(b) नाबार्ड
(c) कृषि लागत एवं कीमत आयोग
(d) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान

17. विश्व में 'हरित क्रांति' के जनक' हैं- **UPPCS Lower (Pre) 2015**
(a) नॉर्मन ई. बोरलॉग (b) एमएस स्वामीनाथन
(c) जीएस खुश (d) बीपी पाल

18. दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है- **UPPCS (Mains) 2014**
(a) प्राथमिक सहकारी सोसाइटी द्वारा
(b) जिला सहकारी बैंक द्वारा
(c) भूमि विकास बैंक द्वारा
(d) राज्य सहकारी बैंक द्वारा

19. किसानों के लिये किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई थी- **UP (RO/ARO) Mains 2014**
(a) 1998-1999 में (b) 1999-2000 में
(c) 2000-2001 में (d) 2001-2002 में

20. निम्न में से किस प्रांत में 'सोयाबीन' खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? **UPPCS (Mains) 2012**
(a) उत्तर प्रदेश (b) बिहार
(c) मध्य प्रदेश (d) महाराष्ट्र

21. उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं- **UPPCS (Mains) 2012**
(a) कृषि क्षेत्र में (b) उद्योग क्षेत्र में
(c) सेवा क्षेत्र में (d) उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में

22. भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ- **UP (RO/ARO) Mains 2012**
(a) 1945 में (b) 1980 में
(c) 1985 में (d) 1988 में

23. 'पीली क्रांति' संबंधित है
(a) पुष्पोत्पादन से
(b) मछली पालन से
(c) तोरिया-सरसों उत्पादन से
(d) गेहूँ उत्पादन से

24. नेफेड (N1AFED) संबंधित है-
    (a) पशुपालन से
    (b) ईंधन की बचत से
    (c) कृषि विपणन से
    (d) कृषि उपकरण से

25. निम्नलिखित पर विचार कीजिये-
    1. सुपारी 2. जौ 3. कॉफी
    4. रागी 5. मूंगफली 6. तिल
    7. हल्दी

    उपर्युक्त में से किनके न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने की है?
    (a) केवल 1, 2, 3 और 7
    (b) केवल 2, 4, 5 और 6
    (c) केवल 1, 3, 4, 5 और 6
    (d) 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7

26. कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) के निम्नलिखित में से कौन-कौन से उद्देश्य हैं?
    1. कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण।
    2. कृषकों के लिये सार्थक वास्तविक आय स्तरों का सुनिश्चय।
    3. लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक कृषि पण्य उचित दरों पर उपलब्ध करवा कर उनके हितों की रक्षा करना।
    4. कृषकों के लिये अधिकतम मूल्य का सुनिश्चय।

    नीचे दिये हुए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिये-
    (a) 1, 2 और 3 (b) 1, 2 और 4
    (c) 1, 3 और 4 (d) 2, 3 और 4

27. गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत (FRP) को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता/करती है?
    (a) आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति
    (b) कृषि लागत और कीमत आयोग
    (c) कृषि मंत्रालय का विपणन और निरीक्षण निदेशालय
    (d) कृषि उत्पाद विपणन समिति

उत्तरमाला

1. (c)	2. (b)	3. (a)	4. (c)	5. (d)	6. (a)	7. (b)	8. (d)	9. (a)	10. (c)
11. (c)	12. (c)	13. (b)	14. (b)	15. (c)	16. (c)	17. (a)	18. (c)	19. (a)	20. (c)
21. (a)	22. (c)	23. (c)	24. (c)	25. (b)	26. (a)	27. (a)			

अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्यों को स्पष्ट करें तथा इस प्रणाली में निहित समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए इसके समाधान के उपायों का विश्लेषण करें।
2. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से आप क्या समझते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों की निम्न आय में कैसे सुधार कर सकता है?
3. बफर स्टॉक क्या है? यह खाद्य सुरक्षा से कैसे संबंधित है? इसके निहित उद्देश्यों पर प्रकाश डालिये।
4. उत्तर प्रदेश में कृषि और बागवानी की स्थिति पर प्रकाश डालिये।
5. "भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 से भारत में भूख और कुपोषण के विलोपन की उम्मीद है।" इस कथन के परिप्रेक्ष्य में भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के क्रियान्वयन पर प्रकाश डालिये।

अध्याय
10

भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग
(Food Processing and Related Industries in India)

भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र उत्पादन, वृद्धि, खपत और निर्यात की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र है। भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में फल और सब्ज़ियाँ, मसाले, माँस और पोल्ट्री, दूध और दूध उत्पाद, मदिरा, मत्स्य उद्योग, वृक्षारोपण, अनाज प्रसंस्करण और उपभोक्ता उत्पाद समूह जैसे मिष्टान्न, चॉकलेट और कोको उत्पाद, सोया आधारित उत्पाद, मिनरल जल, उच्च प्रोटीन खाद्य आदि शामिल हैं। अगस्त 1991 में उदारीकरण से लेकर खाद्य और कृषि-प्रसंस्करण क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर वृद्धि हुई है। इसके अलावा सरकार ने निवेश को ध्यान में रखते हुए संयुक्त उपक्रम, विदेशी सहयोग, औद्योगिकी लाइसेंस और 100% निर्यात उन्मुख इकाइयों के प्रस्ताव स्वीकृत किए हैं। इसके 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का विदेशी निवेश शामिल है।

10.1 खाद्य प्रसंस्करण : अर्थ, कार्यक्षेत्र एवं महत्त्व
(Food Processing : Meaning, Area of Operations and Importance)

भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मुख्यत: निर्यात उन्मुख है। भारत की भौगोलिक स्थिति इसे यूरोप, मध्य एशिया, जापान, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया और कोरिया से संपर्क की अद्वितीय सुविधा प्रदान करती है। विश्व में 72% से अधिक खाद्य की बिक्री सुपर स्टोर्स के माध्यम से होती है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास की काफी संभावनाएँ हैं। साथ ही यहाँ एक बड़े खुदरा व्यापार परिवर्तन के लिये भी अनुकूल स्थिति है।

खाद्य प्रसंस्करण का अर्थ *(Meaning of food processing)*

खाद्य प्रसंस्करण का तात्पर्य खाद्य एवं पेय उद्योग (Food and Beverage Industry) द्वारा प्राथमिक कृषि उत्पादों, पौधों एवं पशुओं से जुड़ी सामग्रियों, जैसे- अनाज, माँस, दूध आदि को उपभोक्ताओं के उपयोग योग्य बनाने से है। यदि चरणबद्ध रूप से खाद्य प्रसंस्करण को समझना हो तो इसे तीन चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके पहले चरण में प्राथमिक कृषि उत्पादों, कच्ची सामग्री, जैसे- दूध, माँस, अनाज, समुद्री खाद्य पदार्थों में पोषक तत्त्वों को मिलाकर, हानिकारक कीटाणुओं को मारकर खाने योग्य बनाया जाता है, यानी प्रसंस्करण इकाइयों या कारखानों द्वारा इनकी संरचना या पोषक स्तर को बदल दिया जाता है। इनमें कई तरह के अन्य घटक (Ingredients) भी मिलाए जाते हैं। दूसरे चरण में इन्हें डिब्बों, कनस्तर या थैलों में पैक किया जाता है और तीसरे चरण में इन्हें उपभोक्ताओं तक पहुँचाया जाता है, जिसे उपभोक्ता आवश्यकतानुसार उपयोग करते हैं। इन खाद्य पदार्थों को पाचनयुक्त बनाने के लिये अत्यधिक प्रसंस्कृत किया जाता है। ये प्रकृति में स्वाभाविक रूप से नहीं पाए जाते। खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण की जटिल प्रक्रिया से गुज़रने के दौरान इनमें कई प्रकार की अतिरिक्त सामग्री मिलाई जाती है, जिससे कि इनकी गुणवत्ता में सुधार हो तथा इन्हें लंबे समय तक खराब होने से बचाया जा सके। इनमें से विषैले तत्त्वों को अलग कर दिया जाता है। इनमें कृत्रिम तरीके से स्वाद बढ़ाने का प्रयास भी किया जाता है, जिसके कारण इनमें कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ भी मिलाए जा सकते हैं।

डिब्बों पर घटक तत्त्वों की सूची देखकर आसानी से पता लगाया जा सकता है कि कोई खाद्य पदार्थ प्रसंस्कृत है या नहीं। यदि घटक तत्त्वों की सूची लंबी है तो इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह एक ज़्यादा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ है। खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण द्वारा इनमें से विषैले तत्त्वों को निकाल दिया जाता है। खाद्य प्रसंस्करण के द्वारा खाद्य निरंतरता, संरक्षण, विपणन तथा वितरण में आसानी होती है और सालभर खाद्य की आपूर्ति बनी रहती है। खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को दूर-दराज़ के क्षेत्रों तक पहुँचाया जा सकता है या वहाँ से लाया जा सकता है। कई तरह के हानिकारक जीवाणुओं को मार दिया जाता है। प्रसंस्करण के माध्यम से खाद्य पदार्थों द्वारा होने वाली बीमारियों को रोका जा सकता है। खाद्य प्रसंस्करण द्वारा पोषक तत्त्वों की कमी को पूरा किया जाता है तथा पोषण स्तर (Nutrition

अध्याय
11

आर्थिक एवं सामाजिक विकास
(Economic and Social Development)

वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में आर्थिक विकास एवं आर्थिक संवृद्धि अत्यंत महत्त्वपूर्ण अवधारणा है। सतत् गतिशीलता एवं अनिवार्य आवश्यकता के रूप में आर्थिक विकास एवं आर्थिक संवृद्धि को आर्थिक चिंतन का केंद्र-बिंदु माना जाता है। आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है, जिसमें देश के समस्त उत्पादन साधनों का कुशलतापूर्वक दोहन किया जाता है। आर्थिक संवृद्धि एवं विकास के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में निरंतर सकारात्मक परिवर्तन होता है। इस प्रक्रिया से जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन होता है। इसलिये आर्थिक विकास एवं आर्थिक संवृद्धि का प्रश्न विकसित, विकासशील एवं अल्प विकसित देशों के लिये समान रूप से महत्त्व रखता है। एक ओर अल्प विकसित देशों एवं विकासशील देशों के लिये निर्धनता, बेरोज़गारी, उत्पादन क्षमता में सुधार एवं उत्तरोत्तर प्रगति के लिये विकास की आवश्यकता महत्त्वपूर्ण है, तो दूसरी ओर विकसित देशों के लिये आर्थिक विकास का महत्त्व इसे निरंतर रूप से बनाए रखने में निहित है।

11.1 आर्थिक एवं सामाजिक विकास की अवधारणा *(Concept of Economic and Social Development)*

किसी भी अर्थव्यवस्था में हो रही आर्थिक क्रियाएँ दीर्घकाल में तीन प्रकार के परिवर्तनों को जन्म देती हैं- आर्थिक विकास, सामाजिक एवं आर्थिक संवृद्धि। आर्थिक विकास में सामाजिक विकास एवं आर्थिक संवृद्धि समाहित रहती है।

आर्थिक विकास *(Economic development)*

आर्थिक विकास से आशय उस प्रक्रिया से है, जिसके परिणामस्वरूप देश के समस्त उत्पादन साधनों का कुशलतापूर्वक दोहन होता है, साथ-ही-साथ राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में निरंतर एवं दीर्घकालिक वृद्धि होती है तथा जीवन स्तर एवं मानव विकास सूचकांक में सुधार की स्थिति उत्पन्न होती है। आर्थिक विकास में गैर-आर्थिक चर को भी शामिल किया जाता है, जैसे- शिक्षा एवं साक्षरता दर, पोषण स्तर, स्वास्थ्य सेवाएँ, जीवन प्रत्याशा तथा लैंगिक समानता आदि। अतः आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है, जिसमें उत्पादन के विभिन्न साधन, जैसे- पूंजी, श्रम, तकनीक आदि एक-दूसरे पर ऐसा अनुकूल प्रभाव डालते हैं जिससे आय वृद्धि के कारण क्रय शक्ति भी बढ़ती है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार, "विकास मानवीय प्रयत्न का परिणाम है, आर्थिक विकास एक सतत् प्रक्रिया है, जिससे राष्ट्रीय आय में निरंतर वृद्धि होती रहती है।"

आर्थिक विकास में कृषि की अपेक्षा उद्योगों, विनिर्माण, सेवा एवं बैंकिंग आदि क्षेत्रों का सकल राष्ट्रीय आय में हिस्सा सर्वाधिक होता है। अमर्त्य सेन ने आर्थिक विकास को अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में परिभाषित किया था, जबकि महबूब-उल-हक ने आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया था।

आर्थिक विकास दर: सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में परिवर्तन की दर 'आर्थिक विकास दर' कहलाती है।

$$\text{आर्थिक विकास दर} = \frac{\text{पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन (वृद्धि या कमी)}}{\text{पिछले वर्ष का सकल घरेलू उत्पाद}} \times 100$$

सामाजिक विकास *(Social development)*

सामाजिक विकास को निश्चित परिभाषा के अंतर्गत समाहित करना कठिन है, क्योंकि यह एक बहुआयामी अवधारणा है। यह एक ओर समाज के गरीब और कमज़ोर वर्ग के विकास से जुड़ी हुई है, जो कि इनके लिये शिक्षा, आवास, क्रयशक्ति

अध्याय
12

समावेशी संवृद्धि तथा सामाजिक न्याय (Inclusive Growth and Social Justice)

प्रत्येक व्यक्ति समाज में समतापूर्ण व्यवहार की अपेक्षा करता है। भारतीय समाज में कई ऐसे वर्ग हैं, जो समाज की मुख्यधारा से बहिष्कृत हैं, जैसे- दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, विकलांग, घुमंतू जातियाँ, महिलाएँ, गरीब, किन्नर एवं शरणार्थी। इन समूहों को समाज की मुख्यधारा में लाना ही सामाजिक समावेशन कहलाता है जिससे समाज का प्रत्येक व्यक्ति विकास की पूर्णता के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। समावेशी संवृद्धि से वित्तीय एवं सामाजिक समावेशन घनिष्ठता के साथ जुड़े हुए हैं। जहाँ **समावेशी संवृद्धि** अंतिम व्यक्ति तक विकास के वितरण को सुनिश्चित करने से संबंधित है, वहीं **सामाजिक समावेशन** समाज के अंतिम व्यक्ति को भी वही महत्त्व दिये जाने की वकालत करता है, जो प्रथम व्यक्ति को प्राप्त है। समावेशी संवृद्धि में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक सभी पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है। सामाजिक समावेशन, समावेशी संवृद्धि का प्रमुख आधार है। समाज में सामाजिक अपवंचन से मुक्ति समावेशी संवृद्धि एवं सामाजिक न्याय के द्वारा ही संभव है।

12.1 समावेशी संवृद्धि : आशय एवं अवधारणा *(Inclusive Growth : Meaning and Concept)*

समावेशी संवृद्धि से आशय आर्थिक विकास की एक ऐसी अवधारणा से है, जिसमें विकास का लाभ समाज के सभी लोगों को समान रूप से प्राप्त हो, कोई भी वर्ग विकास से वंचित न रह जाए, अर्थात् समान अवसरों के साथ-साथ विकास करना ही समावेशी संवृद्धि है।

भारत सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी संवृद्धि (समावेशी विकास) का व्यापक रूप से उपयोग किया। विकास प्रक्रिया को समावेशी बनाने हेतु क्षेत्रीय, सामाजिक तथा आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिये प्रभावी तथा संपोषणीय नीतियाँ एवं कार्यक्रम बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, इसीलिये **बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17)** की अवधारणा का केंद्र–बिंदु **तीव्र, धारणीय और अधिक समावेशी विकास** रखा गया।

योजना बनाने का मुख्य उद्देश्य मानव विकास तथा व्यक्तियों द्वारा जीवन–यापन के उच्चतम स्तर को प्राप्त करना होता है। गरीब एवं हाशिये पर रह रहे लोगों के विकास पर बल, बेहतर रहन-सहन के वातावरण, अवसरों का अधिकतम समान वितरण करने की आवश्यकता है। महिलाओं को केंद्र में रखकर उनके सशक्तीकरण पर बल देते हुए उनकी शिक्षा एवं रोज़गार की ओर ध्यान देना आवश्यक है। जनसंख्या का बड़ा हिस्सा विशेषकर, भूमिहीन कृषि श्रमिक, सीमांत कृषक, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, घुमंतू जातियाँ और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग सामाजिक एवं वित्तीय समस्याओं तथा अपवर्जन से जूझ रहे हैं। ऐसे वर्ग के लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिये सरकार अपनी नीतियों में विशेष उपबंध की व्यवस्था करती है। समावेशी संवृद्धि में आर्थिक विकास की ऊँची वृद्धि दर से प्राप्त लाभ के समान वितरण को शामिल किया जाता है।

समावेशी संवृद्धि स्थापित करने के महत्त्वपूर्ण घटक *(Important components to establish inclusive growth)*

- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी बेरोज़गारों के सामान्य एवं कमज़ोर वर्ग के लिये विशेष उपबंध करना। रोज़गार में वृद्धि को विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ना।
- आधारभूत आवश्यक वस्तुओं तक सबकी पहुँच सुनिश्चित करना।
- कृषि तथा ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करना ताकि इस क्षेत्र में निवेश वृद्धि एवं आय में वृद्धि सुनिश्चित हो सके।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा एवं आवास पर अधिक सार्वजनिक व्यय हो।

अध्याय
13

सतत् विकास
(Sustainable Development)

सतत् विकास एक प्रकार से समाज, पर्यावरण तथा अर्थव्यवस्था का एकीकरण है। यह विकास इस तरह से होता है कि व्यापक संभावित क्षेत्रों, देशों और यहाँ तक कि आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ पहुँचाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमें निर्णय करते समय समाज, पर्यावरण तथा अर्थव्यवस्था पर उसके संभावित परिणामों पर विचार कर लेना चाहिये। हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि हमारे निर्णय एवं कार्य दूसरों को प्रभावित करते हैं तथा हमारे कार्यों का भविष्य पर भी प्रभाव पड़ता है। संक्षेप में सतत् विकास ऐसा विकास है, जो आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किये बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

13.1 सतत् विकास : अर्थ एवं अवधारणा
(Sustainable Development : Meaning and Concept)

'सतत् विकास' शब्द का प्रयोग, 1980 के दशक के अंत में 'हमारा साझा भविष्य' (Our Common Future) नामक रिपोर्ट जिसे द ब्रंटलैंड रिपोर्ट (The Brundtland Report) के नाम से भी जाना जाता है, के आने के बाद व्यापक रूप से किया जाने लगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित आयोग ने विकास के लिये परिवर्तन हेतु वैश्विक प्रारूप का प्रस्ताव पेश किया। ब्रंटलैंड रिपोर्ट ने हमारे रहन-सहन एवं शासन में पुनर्विचार की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। मानवता के लक्ष्यों एवं आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिये पुरानी समस्याओं पर नए तरीके से विचार करने तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं समन्वय पर बल दिया। इस आयोग का औपचारिक नाम पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग (The World Commission on Environment and Development) था। इसने मानव पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के क्षय या खराब होती स्थिति तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये उस क्षय के परिणाम की ओर ध्यान आकृष्ट किया था। आयोग की स्थापना करती समय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विशिष्ट रूप से दो विचारों की ओर ध्यान आकृष्ट किया था-

- पर्यावरण, अर्थव्यवस्था तथा लोगों की भलाई अत्यधिक अंतर्संबंधित हैं।
- सतत् विकास के लिये वैश्विक स्तर पर सहयोग आवश्यक है।

सतत् विकास की संकल्पना हमारे आस-पास तथा विश्व के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में आवश्यक परिवर्तन लाती है और उसी के अनुरूप हम सरकार से निर्णयों की आशा करते हैं। अक्सर सरकारें आर्थिक विकास का त्याग किये बिना विभिन्न प्राकृतिक एवं सामाजिक संसाधनों संबंधी प्रतिस्पर्द्धी मांगों के बीच संतुलन स्थापित करने का कार्य करती हैं, लेकिन ऐसा संतुलन स्थापित करना सरकारों के लिये एक जटिल चुनौती होती है।

सतत् विकास की अवधारणा *(Concept of sustainable development)*

सतत् विकास की संकल्पना के अंतर्गत यह माना जाता है कि आर्थिक संवृद्धि अकेले पर्याप्त नहीं है। किसी कार्य के आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय आयाम अंतर्संबंधित हैं। एक समय में इन तीनों में से केवल एक पर विचार करने से निर्णय में त्रुटि हो सकती है तथा टिकाऊ परिणाम प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐतिहासिक रूप से केवल लाभ पर ध्यान केंद्रित करने से सामाजिक एवं पर्यावरणीय हानि होती है जो दीर्घकाल में समाज को नुकसान पहुँचाती है। लेकिन, पर्यावरण की देखभाल एवं लोगों को सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिये कुछ मात्रा में आर्थिक संसाधन अवश्य चाहियें।

संक्षेप में सतत् विकास से निम्नलिखित लाभ प्राप्त हो सकते हैं:

- आर्थिक संवृद्धि का लाभ सभी नागरिकों को प्राप्त हो सकता है।
- पर्यावरणीय रूप से दूषित औद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों या स्थलों को पारिस्थितिकी अनुकूल शहरी आवासीय परियोजनाओं में बदला जा सकता है।

अध्याय
14

नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के मुद्दे (Issues of Urban and Rural Areas)

विकास परिवर्तन की एक ऐसी सतत् प्रक्रिया है, जो लोगों को इस योग्य बनाती है कि वे सक्षम एवं सृजनात्मक बन सके। विकास सकारात्मक परिवर्तन को इंगित करता है। पिछड़ेपन के साथ मानव विकास संभव नहीं है। इसलिये विकास योजनाएँ मानव विकास तथा उच्चतम जीवन स्तर प्राप्त करने के लिये लक्ष्य करके बनाई जाती हैं। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम की ओर से प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है जिसमें जीवन-स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक समानता आदि मानकों को विकास का प्रमुख वाहक माना जाता है। विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रयास करती है। इस रूप में नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार नीति का प्रतिपादन किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के समग्र विकास को आगे बढ़ाने में नगरीय एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों की महत्त्वपूर्ण एवं समान भूमिका है। चूँकि विकास का प्रमुख वाहक आधारभूत संरचना को माना जाता है। इसलिये आधारभूत संरचना या अवसंरचना के विकास पर प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाता है। अवसंरचना विकास समावेशी विकास, आर्थिक संवृद्धि, निर्धनता कम करने तथा वृहत् विकास लक्ष्यों को पाने के लिये बहुत महत्त्वपूर्ण है।

14.1 नगरीय क्षेत्र के मुद्दे : शहरीकरण से उपजी समस्याएँ *(Issues of Urban Area : Problems Stemming from Urbanization)*

नगरीय क्षेत्र से तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है, जहाँ जनसंख्या घनत्व सघन, अधिकाधिक जनसंख्या की गैर-कृषि कार्य में संलग्नता एवं मानवीय क्रिया-कलाप एक निश्चित क्षेत्र में केंद्रित हो। दूसरे शब्दों में सघन बसे क्षेत्र, जो उद्योग संबंधी कार्यों में संलग्न हैं तथा आर्थिक क्रिया-कलाप के सघनता वाले क्षेत्र हैं, नगरीय क्षेत्र कहलाते हैं। इस क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। नगरीय क्षेत्रों का फैलाव निरंतर होता रहता है।

नगरीय क्षेत्र के लिये निम्नलिखित तत्त्व अनिवार्य है–

1. वैसे क्षेत्र जहाँ न्यूनतम 5000 की जनसंख्या हो।
2. वहाँ कार्यशील जनसंख्या का 75% गैर-कृषि कार्यों में संलग्न हो तथा
3. 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व।

- "नगरीय क्षेत्रों का विस्तार शहरीकरण कहलाता है।" इस भौतिक विस्तार में जनसंख्या, क्षेत्रफल आदि को सम्मिलित किया जाता है। शहरीकरण की प्रक्रिया निरंतर गतिशील रहती है।
- शहरीकरण की प्रक्रिया विकास का सूचक होती है। यहाँ जनसंख्या की अधिकता, घनी आबादी वाली बसावट, श्रमिकों की उपलब्धता, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों के क्रिया-कलापों की तीव्रता जैसी विशेषताएँ पाई जाती हैं।

भारत में शहरीकरण *(Urbanization in India)*

भारत में तीव्रता से शहरीकरण हो रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार 31.2% जनसंख्या शहरों में निवास करती है। भारत में शहरीकरण आधिकारिक रूप से दो मापकों द्वारा परिभाषित किया जाता है– (i) प्रशासनिक परिभाषा, जो शहरी स्थानीय निकायों, जैसे- नगर निगमों, नगर परिषदों, अधिसूचित नगर समितियों आदि द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या पर विचार करती है। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा नियंत्रित शहरी बसावटें सांविधिक शहर कहलाती हैं। प्रशासनिक परिभाषा के प्रयोग के अनुसार, भारत वर्ष 2011 में लगभग 26% शहरी था। राज्य सरकारें बसावट की प्रशासनिक स्थिति निर्धारित करती हैं। पूर्व निर्धारित बसावटें ग्रामीण मानी जाती हैं और वे तभी शहरी बनती हैं, जब अपेक्षित कानूनी प्रक्रिया अपनाने के बाद राज्य सरकारों द्वारा उन्हें परिवर्तित किया जाता है। (ii) जनगणना की परिभाषा के अंतर्गत सांविधिक शहरों और जनगणना शहरों दोनों में रहने वाली जनसंख्या शहरी जनसंख्या कहलाती है। जनगणना शहर वे हैं, जिनमें कम-से-कम 5000 की

अध्याय
15

योजनाएँ एवं विविध (Schemes and Miscellaneous)

एक कल्याणकारी राष्ट्र में गरीबों एवं वंचित वर्गों को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने के लिये सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएँ चलाई जाती हैं। योजनाओं के माध्यम से सरकार आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय एवं आर्थिक संवृद्धि सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। इसी संदर्भ में केंद्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार की कुछ महत्त्वपूर्ण योजनाओं का वर्णन यहाँ किया जा रहा है।

15.1 केंद्र सरकार की योजनाएँ *(Central Government's Schemes)*

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना *(Pradhanmantri Fasal Bima Yojana)*

- इस योजना को 13 जनवरी, 2016 को मंजूरी प्रदान की गई।
- यह योजना वर्ष 2016 के खरीफ सत्र से लागू है।
- प्राकृतिक आपदा (चक्रवात, ओलावृष्टि, बाढ़, सूखा, तूफान इत्यादि), कीटों एवं बीमारियों का प्रकोप व मौसमी गतिविधियों के कारण प्रभावित फसल, बुआई व कटाई के पश्चात् होने वाले नुकसान को इस श्रेणी में रखा गया है।
- किसानों को कृषि क्षेत्र में नवाचार एवं आधुनिक पद्धति को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करना इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है।
- किसानों द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिये केवल 2% तथा रबी फसल के लिये 1.5% का एक समान प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिये प्रीमियम 5% निर्धारित किया गया है।
- भारत सरकार द्वारा 2018–19 के बजट में प्रस्तुत योजना के लिये 13000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

कृषि डाक प्रसार सेवा *(Krishi dak prasar seva)*

- यह केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा किसानों तक बीज पहुँचाने के लिये भारतीय डाक विभाग द्वारा संचालित सेवा है, जिसके तहत चिह्नित किसानों तक आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा उन्नत बीज पहुँचाए जा रहे हैं।
- खेती की उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा तैयार योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य है चिह्नित गाँवों के किसानों तक आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा उन्नत बीजों को डाक के माध्यम से पहुँचाना।
- वर्तमान में यह योजना देश के 14 राज्यों के 100 ज़िलों में शुरू की गई है। इसे कृषि विज्ञान केंद्रों एवं डाकघरों के माध्यम से संचालित किया जाता है।

किसान कॉल सेंटर *(Kisan call center)*

- कृषि में आईसीटी (Information and communication technology) के उपयोग के लिये कृषि मंत्रालय द्वारा 21 जनवरी, 2004 को किसान कॉल सेंटर योजना को प्रारंभ किया गया था। ये कॉल सेंटर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के 14 विभिन्न स्थानों में कार्यरत हैं। इसके लिये देशव्यापी 11 अंकों वाली एक टोल फ्री नंबर-1800-180-1551 जारी किया गया।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं का समाधान स्थानीय भाषा में किसानों को मोबाइल फोन के माध्यम से उपलब्ध कराना है। किसानों के सवालों के जवाब 22 भाषाओं में दिये जाते हैं।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन *(Rashtriya gokul mission)*

भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 28 जुलाई, 2014 को देशी गायों के संरक्षण तथा उनकी नस्लों के विकास को वैज्ञानिक तरीके से प्रोत्साहित करने के लिये राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की गई।

अध्याय
16

आर्थिक अवधारणाएँ तथा शब्दावलियाँ (Economic Concepts and Terminology)

- **आर्बिट्रेज (Arbitrage) :** विभिन्न विदेशी मुद्राओं को एक साथ इस उद्देश्य से खरीदना और बेचना जिससे विश्व के विभिन्न बाज़ारों में विदेशी विनिमय दरों में पाए जाने वाले अंतर से लाभ उठाया जा सके, आर्बिट्रेज कहलाता है।
- **एन्युटी (Annuity) :** किसी एक पूर्व निर्धारित योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष एक या अधिक किस्तों में होने वाला भुगतान एन्युटी कहलाता है, जैसे- सरकारी ऋण-पत्रों पर ब्याज का भुगतान।
- **एडवांस डिक्लाइन (Advance decline) :** यह शेयर बाज़ार की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करने वाला एक माप है। किसी समयावधि में मूल्य वृद्धि को प्रदर्शित करने वाले शेयरों की संख्या का मूल्य ह्रास वाले शेयरों की संख्या के साथ अनुपात ही एडवांस डिक्लाइन कहलाता है।
- **एयर पॉकेट स्टॉक (Air pocket stock) :** यदि किसी कंपनी के शेयरों के पहले दिन के बंद भाव तथा दूसरे दिन के खुलने वाले भाव में काफी अंतर होता है तो वह स्थिति एयर पॉकेट की होती है। यह कई कारणों से घटित होता है। जैसे कि यदि किसी कंपनी के विषय में कोई प्रतिकूल सूचना आती है तो कंपनी के शेयरों के भाव गिर जाते हैं। शेयरों के भाव में उतार-चढ़ाव की स्थिति का होना सामान्य बात है।
- **अग्रिम कर (Advance tax) :** अग्रिम कर प्रत्येक वर्ष मार्च, सितंबर एवं दिसंबर में देय होता है ताकि प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व ही आगामी वित्तीय वर्ष के बजट के संबंध में अपनी राजस्व प्राप्तियों से अवगत हो सके। अग्रिम कर अर्जित आय के आधार पर देय सिद्धांत पर आधारित है।
- **बिटकॉइन (Bitcoin) :** यह समान समूह और जान-पहचान वाले लोगों के बीच इलेक्ट्रॉनिक मनी और पेमेंट नेटवर्क का खुला माध्यम है।
- **आधार प्रभाव (Base effect) :** वर्तमान आँकड़ों की गणना पर पहले के आँकड़ों का पड़ने वाला प्रभाव 'आधार प्रभाव' कहलाता है। स्फीति दर में वृद्धि के संदर्भ में वर्तमान स्फीति दर की गणना पर विगत वर्षों की कीमतों का पड़ने वाला प्रभाव आधार प्रभाव कहलाता है।
- **बूम (Boom) :** अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं की तेज़ी से विस्तार की स्थिति को बूम कहा जाता है। यह स्थिति मंदी के विपरीत है। मांग में वृद्धि के कारण ही किसी उद्योग विशेष में बूम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
- **काला बाज़ार (Black market) :** बाज़ार में जमाखोरी द्वारा वस्तुओं की कृत्रिम कमी पैदा करके उनकी कीमतों को बढ़ाकर लाभ कमाने को काला बाज़ार कहते हैं।
- **काला धन (Black money) :** अवैध तरीकों से अर्जित धन जिसका हिसाब-किताब छिपाकर रखा जाता है, वह काला धन कहलाता है।
- **बुरा ऋण (Bad debt) :** वह ऋण जिसकी वसूली संभव न हो अथवा संदिग्ध हो, बुरा ऋण माना जाता है।
- **ब्रिज लोन (Bridge loan) :** कंपनियाँ प्राय: शेयर तथा डिबेंचर जारी करके पूंजी का विस्तार करती हैं। कंपनी को शेयर जारी करके पूंजी जुटाने में तीन माह या उससे भी अधिक समय लगता है। इस समयावधि में अपना कार्य जारी रखने के लिये कंपनियाँ बैंकों से आंतरिक अवधि के लिये ऋण प्राप्त कर लेती हैं। इस प्रकार के ऋण को ब्रिज लोन कहते हैं।
- **ब्लू चिप (Blue chip) :** जिन कंपनियों का प्रबंध अत्यधिक कुशल तथा सुदृढ़ है, उन कंपनियों के शेयरों के लिये ब्लू चिप शब्द का प्रयोग किया जाता है। इनको बेचने तथा खरीदने में कोई कठिनाई नहीं होती।
- **ब्लू बॉक्स (Blue box) :** कृषि समझौते के अनुसार विभिन्न देश उत्पादन के उद्देश्य से कुछ सीमा तक सब्सिडी की अनुमति देते हैं, जैसे- बिजली, सिंचाई, उर्वरक आदि आगतों में दी जाने वाली सब्सिडी। इस सब्सिडी को ही ब्लू बॉक्स कहते हैं।
- **ब्लू कॉलर जॉब (Blue collar job) :** द्वितीयक क्षेत्र से संबद्ध ऐसे श्रमिकों को जो उत्पादन-प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध होते हैं, उन्हें ब्लू कॉलर जॉब कहा जाता है।

डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी, फ्लोचार्ट तथा मानचित्र का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- क्विक रिवीजन हेतु प्रत्येक अध्याय में महत्त्वपूर्ण तथ्यों का संकलन।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

Website : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

DrishtiIAS
YouTube Drishti IAS
drishtiias
drishtithevisionfoundation

641, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Phones : 011-47532596, +91-8130392354, 813039235456